लड़ाई लंबी पर जीतेंगे हम : मोदी

भाजपा स्थापना दिवस ▶ कहा, कोविड-19 से लड़ाई में डब्लूएचओ भी कर रहा भारत की प्रशंसा

कार्यकर्ताओं को दिए पांच टास्क, भाजपा अध्यक्ष ने कहा- पूरा करेंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा की 40वें स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एएनआइ

कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी लड़ाई का संकेत देते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को पांच टास्क दिए हैं। इसमें गरीबों के लिए भोजन, पानी और राशन से लेकर पीएम केयर्स फंड में खुद के साथ साथ 40 अन्य लोगों से सहयोग करवाने जैसे निर्देश हैं। भाजपा की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरोसा दिलाया है कि पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के सभी निर्देशों को पालन करेंगे।

सोमवार को भाजपा के स्थापना दिवस पर वीडियो के जरिये ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से नेताओं को यह भी संदेश दे दिया कि अगर विपक्ष सरकार के कदमों पर सवाल उठाए तो तथ्यों के साथ उसका जवाब दें। मालूम हो कि पिछले दिनों में विशेषकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सरीखे नेताओं की ओर से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'जब तमाम देश कोरोना की भयावहता का अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहे थे तब भारत एक के बाद एक अनेक फैसले जमीन पर उतार चुका था। भारत ने जितनी गति और समग्रता से काम किया उसकी डब्लूएचओ भी प्रशंसा कर रहा है।' प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा कि लड़ाई लंबी है, लेकिन भारत में इससे जीतने की क्षमता भी है और संकल्प भी। जनता कर्फ्यू से लेकर रविवार को नौ मिनट दीप जलाकर जनता ने यह दिखाया है कि वह कितने अनुशासन के साथ एक लक्ष्य लेकर सामूहिक बल के साथ लड़ने को तैयार है।

कोरोना से लड़ाई में पीएम केयर्स फंड की जरूरत को देखते हुए यूं तो सरकार के स्तर पर भी फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से विशेष भूमिका की अपेक्षा की। उन्होंने हर कार्यकर्ता को भी इसमें योगदान देने के कहा और अन्य 40 को इसके लिए तैयार करने की अपेक्षा भी जताई। ध्यान रहे कि भाजपा सदस्यों की संख्या ही लगभग 18 करोड़ है जबकि सक्रिय सदस्यों की संख्या भी करोड़ों में है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से पहले ही यह निर्देश दिया गया था कि सभी सदस्य कम से कम सौ रुपये का योगदान करें। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण से सतर्क रहने के लिए बनाए गए 'आरोग्य एप' को भी 40 लोगों के मोबाइल में इंस्टाल कराने का निर्देश दिया है। यह एप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आने पर अलर्ट करता है। तीसरा आग्रह डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए धन्यवाद मैसेज है। मास्क कोरोना वायरस से बचाव के लिए अहम माना जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद के साथ-साथ छह-सात अन्य लोगों के लिए मास्क वितरण का निर्देश दिया। यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि हर कार्यकर्ता यह देखे कि उनके आसपास कोई भी भूखा न रहे।

प्रधानमंत्री के संबोधन के तत्काल बाद नड्डा ने भरोसा जताया कि पार्टी हर निर्देश को अमलीजामा पहनाएगी। ध्यान रहे कि भाजपा की ओर से पहले ही रोजाना पांच करोड़ लोगों को खाना देने की एक योजना चल रही है जो 14 अप्रैल तक लागू रहेगी।

सांसद निधि निलंबन के सवाल पर कांग्रेस नेताओं में मतभेद

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- पार्टी रुख से अलग जयराम रमेश ने सरकार के फैसले का किया स्वागत
- रमेश पर भड़के कांग्रेस के लोकसभा सांसद

कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए सांसद निधि को दो साल स्थगित करने के फैसले पर कांग्रेस के अंदर मतभेद खुले तौर पर सामने आ गए हैं। पार्टी ने आधिकारिक रूप से जहां इस पर एतराज उठाया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एमपीलैड के स्थगन का समर्थन किया है। जबकि जयराम के इस रुख से इतर पार्टी के तमाम लोकसभा सांसदों ने सोशल मीडिया पर एमपीलैड को स्थगित करने को तमाम संसदीय क्षेत्रों की जनता के खिलाफ बताया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने तो जयराम रमेश पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी चुनाव न लड़ा हो वही ऐसी बात कर सकता हे।

सांसद निधि के स्थगन को लेकर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के एतराज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम ने अपनी ही पार्टी के थिंक-टैंक और हाईकमान के करीबी माने जाने वाले जयराम रमेश की खुले तौर पर जबरदस्त खिंचाई की। जयराम ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे पहले से कहते रहे हैं कि इस 7000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल सरकारी खर्च पर चुनाव कराने के लिए किया जाना चाहिए।

कार्ति ने जयराम के इस टवीट पर सीधे उन्हें जवाब देते हुए कहा कि ऐसी बात वही कर सकता है जिसने कभी चुनाव न लड़ा हो और उसे कभी जनता को सीधे जवाब नहीं देना पड़ा हो। जयराम पर तंज कसते हुए कार्ति ने कहा कि शहरी मानसिकता वाले लोग इसका स्वागत कर रहे हैं वे उनके संसदीय क्षेत्र शिवगंगा में आकर देखें कि सांसद निधि स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए कितना लाभकारी है। वैसे जयराम का रुख पार्टी के आधिकारिक नजरिये से भी मेल नहीं खाता क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की ओर से सांसद निधि के दो साल के निलंबन को वापस लेने की मांग की है। जयराम की तरह पार्टी के दूसरे राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी भी धीमे सुर में एमपीलैड के निलंबन का समर्थन करते हुए दिखे और कहा कि शायद ऐसा करना जरूरी हो। हालांकि इसके विपरीत कांग्रेस के तमाम लोकसभा सांसद मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम, तरुण गोगोई और मणिक्कम टैगोर ने जयराम के रुख से उलट सोशल मीडिया पर खुलकर एमपीलैड के स्थगन का विरोध किया। शशि थरूर ने तो बिना देरी किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि बेशक एमपीलैड की यह राशि कोरोना महामारी से लड़ाई में खर्च की जाए मगर यह स्थानीय स्तर पर सांसदों के इलाके में ही हो और इस राशि को केंद्र की समेकित निधि में शामिल करने के फैसले पर पुनर्विचार हो।

न्यूज गैलरी

'मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन स्थापित करें विवि व कॉलेज'

नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को दूर करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन की स्थापना के निर्देश दिए हैं। यूजीसी सचिव रजनीश जैन की तरफ से कुलपतियों को भेजे गए पत्र के अनुसार, 'कोरोना संक्रमण के कारण जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक चिंताओं का निवारण बहुत जरूरी है, इसलिए विवि और कॉलेज मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्रों के किसी भी प्रकार के तनाव और भय को दूर करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन की स्थापना करें।' (प्रेट्र)

अगस्ता मामले में मिशेल की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मिशेल के अधिवक्ता के साथ ही सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। (जासं)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सभी अदालतें वीडियो कांफ्रेंसिंग से करें सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश
- अदालतें सुनिश्चित करें कि परिसर संक्रमण फैलने का जरिया न बने

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (बीच में) की पीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करती हुई। एएनआइ

कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक दूरी बनाए रखने और अदालतों में भीड़ नहीं जुटाने की बात कहते हुए देश की सभी अदालतों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लॉकडाउन के चलते उत्पन्न स्थिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ये दिशा-निर्देश मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव की पीठ ने दिए। कोर्ट ने कहा कि महामारी से उपजी विकट स्थिति में जरूरी है कि अदालतें हर स्तर पर शारीरिक दूरी का पालन कर सुनिश्चित करें कि अदालत परिसर संक्रमण फैलने का जरिया न बने। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अदालत परिसर में लोगों की शारीरिक उपस्थिति कम करने के लिए जो नियम बनाए हैं, वे सभी कानूनी माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये न्यायिक कार्य के लिए जरूरी कदम उठाने को अधिकृत हैं। मौजूदा स्थिति और जन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक हाई कोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के अस्थायी तौर-तरीके तय कर सकता है। संबंधित कोर्ट इस बारे में एक हेल्पलाइन भी बनाएगा, जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सुनाई देने आदि के बारे में शिकायत की जा सके। इस संबंध में कोई भी शिकायत सुनवाई के दौरान या उसके तुरंत बाद ही सुनी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रत्येक राज्य की जिला अदालतें संबंधित हाई कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करेगी। अगर किसी केस में जरूरी हो तो अदालत एमीकस क्यूरी नियुक्त कर सकती है और उस वकील के जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक संबंधित हाई कोर्ट इस संबंध में उचित नियम नहीं बनाता ट्रायल और अपीलीय दोनों स्तरों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बहस होगी। किसी भी मामले में दोनों पक्षों की सहमति के बगैर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही या साक्ष्य दर्ज नहीं किए जाएंगे। अगर अदालत कक्ष में साक्ष्य दर्ज करना जरूरी हो तो पीठासीन जज दो लोगों के बीच उचित दूरी बनाए रखने का ध्यान रखेंगे। पीठासीन जज को अदालत कक्ष में लोगों का प्रवेश नियंत्रित करने का अधिकार होगा।

विपक्षी पार्टियां एमपीलैड के स्थगन के खिलाफ

फंड पर खींचतान

- कांग्रेस ने कहा-सांसद निधि के निलंबन से स्थानीय जनता को दिक्कत
- माकपा, तृणमूल कांग्रेस और आप ने भी किया विरोध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विपक्षी दलों ने कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए मंत्रियों-सांसदों के वेतन में कटौती का तो समर्थन किया है। मगर सांसद निधि फंड को दो साल के लिए स्थगित करने का विरोध किया है। इन दलों का कहना है कि एमपीलैड को निलंबित करने से स्थानीय स्तर पर कोरोना जैसी महामारी या अन्य प्राकृतिक आपदा ही नहीं जनता से जुड़े छोटे-मोटे विकास कार्यों का रास्ता बंद हो जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि सांसद निधि बंद करने के बजाय केंद्र सरकार को अपने गैरजरूरी खर्च में कटौती कर इस रकम को कोरोना से लड़ाई में लगाना चाहिए।

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना से लड़ने का संसाधन जुटाने के लिए सांसदों के वेतन में पचास फीसद तक कटौती कर लेते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एमपीलैड सांसदों का कोई निजी कोष नहीं होता बल्कि स्थानीय स्तर पर यह जनता की भलाई के कार्यों के लिए होता है।

सुरजेवाला ने कहा कि इसे निलंबित करने से जहां एक ओर स्थानीय स्तर पर जनता के जरूरी विकास कार्य रूक जाएंगे वहीं सांसदों की भूमिका पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। अगर देश के सांसदों की आवाज ही चली गई तो लोकतंत्र में संसद की प्रभावी भूमिका भी कम हो जाएगी।

कांग्रेस की मांग है कि सांसद निधि को बहाल किया जाए। कांग्रेस के दूसरे नेता मनीष तिवारी ने भी वेतन में कटौती का समर्थन किया मगर सांसद निधि को निलंबित करने के फैसले को जनता के हितों के खिलाफ करार दिया। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को कोरोना से पहले ही आर्थिक मुश्किलों में ला खड़ा किया था और सरकारी धन का दुरुपयोग गैरजरूरी प्रचार और कामों में किया। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का विकल्प अपना रही है। तृणमूल कांग्रेस ने भी बयान जारी कर एमपीलैडस को दो साल के लिए स्थगित करने का विरोध किया।

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने भी कहा कि सरकार का यह फैसला अनुचित है और यह कदम उठाने से पहले सांसदों से मशविरा करना चाहिए था।

सांसदों का वेतन

वेतन	भत्ते - राशि
मूल वेतन	1,00,000 रुपये प्रतिमाह
चुनाव क्षेत्र भत्ता	70,000 रुपये प्रतिमाह
ऑफिस खर्च भत्ता	60,000 रुपये प्रतिमाह
फर्नीचर भत्ता	1,00,000 रुपये (पांच साल में एक बार)
कटौती	30,000 रुपये प्रतिमाह (मूल वेतन का 30 फीसद)

लॉकडाउन में भारत ने राजनीति व धर्म के बिना जीना सीखा : माधवन नायर

- कहा, हर चुनाव के बाद अपनाया जाना चाहिए ऐसा ही रुख

बेंगलुरु, प्रेट्र : देश के प्रख्यात वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व चेयरमैन जी. माधवन नायर ने कहा है कि लॉकडाउन में देश ने राजनीति और धर्म के बिना जीना सीख लिया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माधवन नायर ने कहा कि यह ट्रेंड जारी रहना चाहिए, हर चुनाव के बाद राजनीतिक गतिविधियां पृष्ठभूमि में चली जानी चाहिए और हर व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोविड-19 पर उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर ऐसे कई वायरस निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और जब स्थितियां अनुकूल होती हैं तो वे सक्रिय हो जाते हैं। अगर आप पिछली तीन सदियों या उससे पीछे के समय को देखें तो हर सौ वर्ष में एक बार कुछ न कुछ जरूर फैलता है। इसलिए यह प्राकृतिक घटना है। इसमें सतर्क रहने की जरूरत है।

राष्ट्र निर्माण में भी दिखानी होगी ऐसी एकजुटता : नायर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों ने जाति, पंथ और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर अपनी एकजुटता दिखाई है।

जी. माधवन नायर फाइल फोटो

राष्ट्र निर्माण में भी यही रुख अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरस का प्रसार रोकने के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न कदमों को बड़े पैमाने पर नौकरशाही द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसने इस मौके पर बहुत बढ़िया काम किया है। यही भावना बरकरार रखनी होगी।

स्वदेशीकरण कार्यक्रम के लिए अच्छा समय : भारत में बहुत बड़े घरेलू बाजार का उल्लेख करते हुए पूर्व इसरो प्रमुख जी. माधवन नायर ने स्वदेशीकरण कार्यक्रम पर जोर देने की वकालत की जो पिछले कुछ समय से विदेश में आसानी से उपलब्ध वस्तुओं की वजह से पृष्ठभूमि में चला गया था। नायर ने कहा, 'भारतीय उद्योगों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए अब समय है कि वे स्वदेशीकरण अभियान को तेज गति प्रदान करें।'

बिचौलियों का खात्मा देश के लिए अच्छा

नायर ने कहा कि लोगों के लिए कोविड-19 राहत पैकेज लाने में भारत बिचौलियों को खत्म करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा, 'पहले सभी तरह की आर्थिक सहायता बिचौलियों के हाथों में चली जाती थी और वे लोग उसके लाभों से वंचित हो जाते थे जिन तक उसे पहुंचना होता था। इसलिए यह प्रक्रिया (बिचौलियों के खात्मे की) अगर जारी रहती है तो यह निश्चित तौर पर देश के लिए अच्छी है।'

उपज बेचने में किसानों की मदद करें

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से यह भी कहा, 'उन स्थानों पर विभागों को धीरे-धीरे खोलने के लिए एक श्रेणीबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए जहां हॉटस्पॉट मौजूद नहीं हैं।' देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। इसके बाद उपज बेचने की बारी आएगी। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को इसमें किसानों का सहयोग करने की अपील की। इसके तहत मंडियों से किसानों को जोड़ने के लिए एप आधारित कैब सेवाओं की तर्ज पर 'ट्रक एग्रीगेटर्स' जैसे नए समाधान की संभावनाएं तलाशें। लॉकडाउन उपाय के साथ शारीरिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों पर एक साथ अमल करने की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने पर प्रत्येक मंत्रालय के लिए 10 प्रमुख निर्णयों और फोकस वाले 10 प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालय इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ें। बैठक में मंत्रियों ने कोरोना महामारी के प्रभावों की चुनौतियों का जिक्र करने के साथ ही उन चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

देशभर में लागू हो सकता है कोरोना से बचाव का 'भीलवाड़ा माडॅल'

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस से निपटने को लेकर अपनाई गई नीति पूरे देश में लागू हो सकती है । केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से इसको लेकर विस्तृत जानकारी मांगी। इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट सचिव गौबा ने कोरोना से बचाव के लिए भीलवाड़ा में किए गए उपायों की तारीफ करते हुए इस मॉडल को देशभर में लागू करने के संकेत दिए है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इस बारे में प्रदेश में चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह से जानकारी मांगी है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा में कोरोना का प्रकोप मार्च के तीसरे सप्ताह में एक साथ फैला तो सरकार ने घर-घर स्क्रीनिंग शुरू की। इस दौरान 18 लाख लोगों की जांच की गई । इसके लिए 15 हजार टीमें बनाई गई थीं। पहले लॉकडाउन और फिर कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया गया । पॉजिटिव पाए गए लोगों को तत्काल आइसोलेट किया गया । क्वारंटाइन किए गए लोगों के घरों के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया, जिससे वे बाहर नहीं निकल सकें। शर्मा ने बताया कि इससे पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज को लेकर यहां के चिकित्सकों ने जो दवाइयां काम में ली थीं, उनके बारे में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी मांगी थी । उन दवाइयों के कारण कई मरीज स्वस्थ्य हुए हैं।

किसी को नहीं दिया प्रवेश : भीलवाड़ा में जब हालात बिगड़े तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, मीडियाकर्मियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शहर में प्रवेश नहीं दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस के भी कुछ ही अधिकारी शहर में गए। लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करवाने पर जोर दिया गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना मनोबल ऊंचा रखा। इसका असर भी दिखा और कई संक्रमित मरीज ठीक हो गए ।

अनुराग श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का प्रभार संभाला

नई दिल्ली, प्रेट्र : वरिष्ठ राजनयिक अनुराग श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का प्रभार संभाल लिया है। उन्होंने रवीश कुमार की जगह ली है। भारतीय विदेश सेवा में 1999 बैच के अधिकारी इससे पहले इथोपिया में भारत के राजदूत थे।

अनुराग श्रीवास्तव। फाइल

प्रभार संभालने के बाद अनुराग ने ट्वीट किया, 'एटएमईएंडिया के अधिकृत प्रवक्ता का प्रभार संभाल कर सम्मान और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। इस नई भूमिका में अपनी सभी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए काम करने की इच्छा रखता हूं।' इथोपिया में भारतीय राजदूत नियुक्त होने से पहले अनुराग विदेश मंत्रालय के वित्त डिवीजन के प्रबंधन का काम कर रहे थे। इसी विभाग पर करोड़ों रुपये के सालाना बजट के प्रशासन का भार है। अनुराग जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत की भी भूमिका निभा चुके हैं। वहां उन्होंने मानवाधिकार से संबंधित काम, शरणार्थी मुद्दे और व्यापार नीति पर काम किया।

बदलाव

प्रतिवर्ष चयनित स्वयंसेवकों के लिए लगता है प्रशिक्षण शिविर, इस बार पूरे देश में 92 से अधिक स्थानों पर लगना था शिविर, कोरोना संक्रमण को केंद्र में रख जून तक नहीं होंगे सामूहिक कार्यक्रम

आरएसएस ने पहली बार अपने संघ शिक्षा वर्ग को किया स्थगित

संजय कुमार, रांची

कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने में प्रशासन और समाज का सहयोग कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जून तक अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया हैं। यह पहली बार है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के संघ शिक्षा वर्ग को स्थगित कर दिया गया है। 20 से 25 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इस बार 92 से अधिक स्थानों पर होना था। 23 हजार से अधिक स्वयंसेवक इसमें भाग लेने वाले थे।

आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने दैनिक जागरण से कहा कि अभी अधिकतर स्वयंसेवक पूरे देश में राहत कार्य चलाने में लगे हैं। आगे कैसी परिस्थिति बनेगी, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इस बार प्रशिक्षण शिविर, योजना बैठक सहित सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। बताते चलें कि संघ अपने स्वयंसेवकों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष संघ शिक्षा वर्ग लगाता है। पिछले बार 19000 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण लिया था। यह काम 1929 से चल रहा है।

तृतीय वर्ष के समापन समारोह में पूर्व राष्ट्रपति भी हुए थे शामिल : एक सप्ताह का प्राथमिक शिक्षा वर्ग करने वाले स्वयंसेवकों को प्रथम वर्ष के शिविर में भेजा जाता है, जो सभी प्रांतों में लगता है। प्रथम वर्ष प्रशिक्षित को द्वितीय वर्ष के शिविर में भेजा जाता है जिसमें दो से तीन राज्य से स्वयंसेवक भाग लेते हैं। द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक को तृतीय वर्ष में भेजा जाता है जो केवल आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में ही लगता है। इसमें पूरे देश के स्वयंसेवक भाग लेते हैं। 2018 के तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल हुए थे।

अप्रैल से शुरू होकर जून तक चलता है शिविर : संघ शिक्षा वर्ग का आयोजन सभी राज्य अपने यहां के मौसम को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जहां मॉनसून पहले आता है वहां पहले इसका आयोजन किया जाता है। केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 15 अप्रैल से ही इसकी शुरुआत होनी थी। वहीं पंजाब में जून में आयोजित किया जाता है। इस शिविर में 20 दिनों तक स्वयंसेवक कड़ी मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक उनका प्रशिक्षण चलता है।

25 सेवा कार्य चला रहा संघ

प्रथम पृष्ठ से आगे

सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कहा कि देश में आई इस विपदा की घड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रात दिन जरूरतमंदों की मदद को आगे आ रहे हैं। इस समय देश भर में 26 हजार स्थानों पर संघ के दो लाख स्वयंसेवक सेवा कार्यों में लगे हैं। इन सेवा कार्यों से अबतक 25 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। इसके तहत 25 प्रकार के सेवा कार्य चल रहे हैं। कई स्थानों पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन सेवा कार्यों में लोगों को भोजन, चिकित्सा सुविधा और दूसरी तरह की सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

वैद्य ने कहा कि भोजन कराने के साथ-साथ देश में कई जगहों पर कोरोना से बचाव के लिए सेफ्टी ड्रेस का निर्माण किया जा रहा है। कई स्वयंसेवक परिवार मास्क बनाकर भी दे रहे हैं। लोगों को सुरक्षा के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा और होम्योपैथिक दवाइयां भी दी जा रही हैं। अलग-अलग स्थानों पर दूध- सब्जी फल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सेवा के इस कार्य में सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, सक्षम, नेशनल मेडिकल आर्गनाइजेशन, भाजपा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ, आरोग्य भारती, हिंदू जागरण मंच, जैसी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी